

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 17

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	51.65	117981.14	118032.79	124.75	125000.00	125124.75	93.36	140400.00	140493.36	100.00	139998.40	140098.40
पूँजी	88.92	...	88.92	87.25	...	87.25	71.64	...	71.64	50.00	1.60	51.60
जोड़	140.57	117981.14	118121.71	212.00	125000.00	125212.00	165.00	140400.00	140565.00	150.00	140000.00	140150.00
(करोड़ रुपए)												
ब.अ. 2016-2017												
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	51.85	51.85
2. राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर	2408	22.39	22.39
	4408	1.60	1.60
	जोड़	23.99	23.99
3. खाद्य सब्सिडी												
3.01 खाद्य सब्सिडी	2408	134834.61	134834.61
3.02 भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम	6408	10000.00	10000.00
3.03 एफसीआई को अर्थोपाय अग्रिम का भुगतान	6408	-10000.00	-10000.00
	कुल	134834.61	134834.61
4. आंतर राज्य आवाजाही, खाद्यान्नों की व्यवस्था तथा एनएफएसए के अंतर्गत एफपीएस डीलरों की माजिन पर व्यय पूरा करने के लिए सहायता	2408	76.00	76.00
	3601	2200.00	2200.00
	3602	224.00	224.00
	जोड़	2500.00	2500.00
5. खाद्य तेलों के आयात पर सब्सिडी - पिछली देनदारियां	2408	567.01	567.01
6. चीनी उद्योग का विकास												
6.01 चीनी विकास निधि को अंतरण	2408	2000.00	2000.00
6.02 एसडीएफ से वित्तपोषित योजनाएं												
6.02.01 चीनी उपक्रमों/एसडीएफ के अन्य व्यय के लिए वित्तीय	2408	21.60	21.60

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
6.02.02 सहायता चीनी मिलों के पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण हेतु ऋण	6860	150.00	150.00
6.02.03 गन्ना विकास हेतु चीनी मिलों को ऋण	6860	75.00	75.00
6.02.04 बागासी आधारित सहसृजन विद्युत परियोजना के लिए चीनी मिलों को ऋण	6860	200.00	200.00
6.02.05 अल्कोहोल से निर्जलीय अल्कोहोल अथवा इथनोल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को ऋण	6860	125.00	125.00
6.02.06 चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने की योजना (सेफासु 2014)	2408	800.00	800.00
6.02.07 कच्ची चीनी उत्पादन के लिए विपणन और संवर्धन सेवाओं हेतु प्रोत्साहन	2408	30.00	30.00
6.02.08 चीनी मिलों को किफायती ऋण देने की योजना पर ब्याज माफी, 2015	2408	202.50	202.50
6.02.09 गन्ना लागत प्रतिसंकुलित करने और किसानों देय गन्ना मूल्य के समय पर भुगतान हेतु चीनी मिलों को उत्पादन सब्सिडी	2408	950.01	950.01
6.02.10 चीनी विकास निधि से पूरा किया गया	2408	-2004.11	-2004.11
	6860	-550.00	-550.00
	जोड़	-2554.11	-2554.11
	कुल
जोड़- चीनी उद्योग का विकास		2000.00	2000.00
7. भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण तथा खाद्य भंडारण के अन्य कार्यक्रम	2408	18.00	22.54	40.54
8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालनों का सुदृढीकरण	2408	2.40	...	2.40
	2552	25.39	...	25.39
	3456	4.57	...	4.57
	3601	47.13	...	47.13
	3602	0.51	...	0.51
	जोड़	80.00	...	80.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
9. भंडार और भंडारगृह	2552	2.00	...	2.00
	4552	50.00	...	50.00
	जोड़	52.00	...	52.00
सं.अ. 2015-2016												
10. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	3451	...	37.87	37.87	...	42.22	42.22	...	42.20	42.20
खाद्य, भंडारण और भांडागारण												
11. खाद्य सस्मिडी												
11.01 खाद्य सस्मिडी	2408	...	57295.35	57295.35	...	59500.00	59500.00	...	59500.00	59500.00
11.02 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए अतिरिक्त प्रावधान	2408	...	60375.81	60375.81	...	64919.00	64919.00	...	79919.00	79919.00
	जोड़- खाद्य सस्मिडी	...	117671.16	117671.16	...	124419.00	124419.00	...	139419.00	139419.00
12. चीनी के बफर स्टॉक के अनुरक्षण पर सस्मिडी	2408	...	4.94	4.94	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
13. चीनी के निर्यात लदान हेतु चीनी मिलों को आंतरिक परिवहन एवं भाड़ा शुल्क की प्रतिपूर्ति	2408	0.01	0.01
14. खाद्य तेलों के आयात से संबद्ध सस्मिडी	2408	150.00	150.00
15. चीनी उपक्रम को वित्तीय सहायता देने के लिए योजना, 2014	2408	...	703.77	703.77	...	800.00	800.00	...	800.00	800.00
16. कच्ची चीनी के उत्पादन के लिए विपणन और प्रोत्साहन सेवाओं पर प्रोत्साहन	2408	...	183.87	183.87	200.00	200.00
17. चीनी मिलों को किफायती ऋण देने की योग्यता पर ब्याज माफी, 2015	2408	202.50	202.50
18. चीनी उद्योग के विकास से संबद्ध अन्य व्यय	2408	...	21.22	21.22	...	22.54	22.54	...	21.34	21.34
19. चीनी विकास निधि												
19.01 को अंतरण	2408	...	250.00	250.00	...	500.00	500.00	...	750.00	750.00
19.02 से	2408	...	-913.79	-913.79	...	-825.55	-825.55	...	-1226.84	-1226.84
	6860	...	-396.45	-396.45	...	-500.00	-500.00	...	-457.57	-457.57
	जोड़	...	-1310.24	-1310.24	...	-1325.55	-1325.55	...	-1684.41	-1684.41
	कुल	...	-1060.24	-1060.24	...	-825.55	-825.55	...	-934.41	-934.41
20. खाद्य, भंडारण और भांडागारण के अन्य कार्यक्रम												
20.01 खाद्य, भंडारण और भांडागारण के अन्य कार्यक्रम	2408	15.23	17.49	32.72	30.85	20.22	51.07	15.85	17.92	33.77
	3601	5.00	...	5.00
	जोड़	20.23	17.49	37.72	30.85	20.22	51.07	15.85	17.92	33.77
20.02 राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर	2408	0.25	16.23	16.48	0.25	18.56	18.81	0.25	18.09	18.34
	4408	2.08	...	2.08	2.25	...	2.25	3.25	...	3.25

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
जोड़	2.33	16.23	18.56	2.50	18.56	21.06	3.50	18.09	21.59
जोड़- खाद्य, भंडारण और भांडागारण के अन्य कार्यक्रम	22.56	33.72	56.28	33.35	38.78	72.13	19.35	36.01	55.36
21. भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम												
21.01 अर्थोपाय अग्रिम	6408	10000.00	10000.00	...	10000.00	10000.00	...	20000.00	20000.00
21.02 घटाएं : प्राप्तियां	6408	-10000.00	-10000.00	...	-10000.00	-10000.00	...	-20000.00	-20000.00
कुल
जोड़-खाद्य, भंडारण और भांडागारण	22.56	117558.44	117581.00	33.35	124457.78	124491.13	19.35	139897.44	139916.79
नागरिक आपूर्ति												
22. खाद्यान्न प्रबंधन का विकास, मानीटरिंग और अनुसंधान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	3456	0.49	...	0.49	1.02	...	1.02	0.82	...	0.82
	3601	0.36	...	0.36	0.57	...	0.57	0.53	...	0.53
	3602	0.01	...	0.01
जोड़	0.85	...	0.85	1.60	...	1.60	1.35	...	1.35
23. टीपीडीएस संचालनों का एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण	3456	2.08	...	2.08	4.93	...	4.93	4.30	...	4.30
	3601	29.60	...	29.60	63.82	...	63.82	47.55	...	47.55
	3602	1.40	...	1.40	1.25	...	1.25	0.12	...	0.12
जोड़	33.08	...	33.08	70.00	...	70.00	51.97	...	51.97
जोड़-नागरिक आपूर्ति	33.93	...	33.93	71.60	...	71.60	53.32	...	53.32
उपभोक्ता उद्योग												
24. सरकारी उद्यमों में निवेश	4408	86.84	...	86.84	10.00	...	10.00
25. चीनी कारखानों का सुधार/ आधुनिकीकरण	6860	...	200.00	200.00	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00
26. गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण	6860	...	72.93	72.93	...	75.00	75.00	...	30.74	30.74
27. बगैस आधारित-सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी मिलों को ऋण	6860	...	46.45	46.45	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00
28. एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथनाल के उत्पादन के लिए चीनी मिलों को ऋण	6860	...	77.07	77.07	...	75.00	75.00	...	76.83	76.83
जोड़-उपभोक्ता उद्योग	86.84	396.45	483.29	10.00	500.00	510.00	...	457.57	457.57
29. गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ करना	2408	2.72	...	2.72	5.00	...	5.00	3.50	...	3.50
खाद्य, भंडारण और भांडागारण												
30. राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य खाद्य आयोग को नॉन बिल्डिंग के लिए सहायता	2408	0.28	...	0.28
	3601	1.16	...	1.16	0.75	...	0.75
	3602	0.12	...	0.12
जोड़	1.56	...	1.56	0.75	...	0.75

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
31. आंतरराज्य आवाजाही, खाद्यान्नों की व्यवस्था तथा एनएफएसए के तहत एफपीएस डीलरों की मार्जिन पर व्यय पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्यों को सहायता	2408	1.00	1.00	
	3601	1.78	1.78	
	3602	0.01	0.01	
	जोड़	2.79	2.79	
जोड़-खाद्य, भंडारण और भांडागारण	1.56	...	1.56	0.75	2.79	3.54	
32. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ की परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	15.49	...	15.49	19.69	...	19.69	
	4552	75.00	...	75.00	68.39	...	68.39	
	जोड़	90.49	...	90.49	88.08	...	88.08	
33. वास्तविक वसूलियां	2408	...	-11.58	-11.58	
	3451	...	-0.04	-0.04	
	3601	-5.48	...	-5.48	
	जोड़	-5.48	-11.62	-17.10	
कुल जोड़		140.57	117981.14	118121.71	212.00	125000.00	125212.00	165.00	140400.00	140565.00	150.00	140000.00	140150.00
	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
18.01 भारतीय खाद्य निगम	12408	86.84	...	86.84	10.00	...	10.00
18.02 केंद्रीय भांडागारण निगम	12408	...	110.37	110.37	...	608.52	608.52	...	180.84	180.84	...	190.04	190.04
18.03 भारतीय खाद्य निगम	22552	75.00	...	75.00	68.39	...	68.39	50.00	...	50.00
जोड़		86.84	110.37	197.21	85.00	608.52	693.52	68.39	180.84	249.23	50.00	190.04	240.04
ग. योजना परिव्यय													
1. खाद्य, भंडारण तथा भांडागारण	12408	112.12	110.37	222.49	49.91	608.52	658.43	23.60	180.84	204.44	20.40	190.04	210.44
2. नागरिक आपूर्ति	13456	28.45	...	28.45	71.60	...	71.60	53.32	...	53.32	52.21	...	52.21
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	90.49	...	90.49	88.08	...	88.08	77.39	...	77.39
जोड़		140.57	110.37	250.94	212.00	608.52	820.52	165.00	180.84	345.84	150.00	190.04	340.04

1. सचिवालय व्यय: यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर:** इसमें प्रशिक्षण (राष्ट्रीय शर्करा संस्थान से संबंधित स्थापना व्यय) एवं राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में किण्वन और आसवन इकाई तथा विश्लेषणात्मक उपकरणों को स्थापित करने के लिए प्रावधान शामिल है।

3.01. **खाद्य सस्मिडी:** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए आवंटन सहित खाद्य राजसहायता का मदवार आवंटन इस प्रकार है:

(क) भारतीय खाद्य निगम टीपीडीएस के साथ-साथ भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतें पूरी करने के लिए सस्मिडी। (रुपये 103334.61 करोड़)।

(ख) राज्य सरकारों को सस्मिडी का भुगतान किया जाता है, जो खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के अंतर्गत केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद कर रहे हैं। (रुपये 27000.00 करोड़)।

(ग) भारत सरकार उन राज्य सरकारों को, जो खुदरा निर्गम मूल्य को रुपये 13.50 प्रति किलो की दर पर जारी रखें हुए हैं, रुपये 18.50 प्रति किलो की दर से वर्तमान आवंटन की मात्र के लिए चीनी पर सस्मिडी प्रदान करेगी। भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति वर्तमान आवंटन के स्तर तक की मात्र तक सीमित होगी। (रुपये 4500.00 करोड़)।

3.02. **भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के लिए खाद्यान्न की खरीद के सम्बन्ध में अपनी नकद धन की प्रवाह आवश्यकताओं की पूर्ति, बफर स्टॉक आवश्यकताओं और खाद्यान्न के रखरखाव हेतु अर्थोपाय अग्रिम है। इस अग्रिम को उसी वित्त वर्ष में समायोजित कर लिया जाएगा।

4. **राज्य-सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र को सहायता ::** यह प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों के रखरखाव, अंतर्राज्यीय संचलन और उचित दर दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु राज्य-सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए है।

5. **खाद्य तेल के आयात पर सस्मिडी - विगत देयताएं:** यह प्रावधान खाद्य तेल राजसहायता के बकाये का 3 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भुगतान करने के लिए है जिन्होंने 'राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्य तेल का आयात करने की योजना, जिसमें भारत सरकार से 15 रुपये प्रति किलो राजसहायता सामिल है' के तहत खाद्य तेलों का आयात किया था।

6.01. **चीनी विकास निधि को अंतरण:** चीनी उपकर अधिनियम, 1982 के अंतर्गत भारत की समेकित निधि में जमा करने के लिए चीनी के उत्पादन पर उपकर लगाने की व्यवस्था है, जो की 1 फरवरी, 2016 से 124 रुपए प्रति क्विंटल है। चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में एकत्रित उपकर में से इसकी एकत्रण लागत घटाकर बची राशि के बराबर को चीनी विकास निधि में जमा कराने की व्यवस्था है जिसका उपयोग ऋण अनुदान देकर और चीनी उद्योग के विकास से संबंधित अन्य खर्च पूरे करके चीनी उद्योग के विकास और उससे संबंधित मामलों अथवा उससे संबंधित प्रासंगिक खर्च को पूरा करने के लिए किया जाना

है। भारतीय लोक लेखा के अंतर्गत चीनी विकास निधि को भारत की समेकित निधि से उपर्युक्त विधि से आकलित राशि अंतरित करने और निधि से आहरण की व्यवस्था है।

6.02.01. **चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता/चीनी विकास निधि से संबंधित अन्य व्यय:** यह व्यय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को एजेंसी कमीशन के भुगतान करने के लिए चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है और इसमें चीनी मिलों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान भी शामिल है।

6.02.02. **चीनी कारखानों के पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण के लिए ऋण:** यह व्यय चीनी कारखानों के पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण के लिए रियायती ऋण देने के लिए है और इसे चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है।

6.02.03. **गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण:** यह प्रावधान गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने के लिए है और इसकी पूर्ति चीनी विकास निधि से की जाती है।

6.02.04. **खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी कारखानों को ऋण:** यह प्रावधान खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी कारखानों को रियायती ऋण देने हेतु है और इसे चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है।

6.02.05. **एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथेनाल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को ऋण:** यह प्रावधान एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथेनाल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को रियायती ऋण देने के लिए किया गया है और इसे चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है।

6.02.06. **चीनी इकाईयों को वित्तीय सहायता देने हेतु स्कीम, 2014:** रु 800 करोड़ का प्रावधान सभी भागीदार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को चीनी कारखानों की हालत में सुधार करने के मद्देनजर, उन्हें पूर्व में चीनी मौसमों के बकाया को चुकाने और केन्द्र सरकार द्वारा गन्ना किसानों के लिए नियत उचित और लाभप्रद मूल्य संबंधी गन्ना मूल्यों का समय पर निपटान करने के लिए ब्याज से बचने के लिए है। सामान्य बैंकिंग प्रथा के अनुसार ब्याज सर्वेशन, जिसकी सीमा 12 प्रतिशत वार्षिक है, लोन की अवधि के लिए ही है। जो मोरेटोरियम के दो वर्ष सहित पांच वर्ष है। इस व्यय को चीनी विकास निधि से पूरा किया जाएगा।

6.02.07. **कच्ची चीनी के उत्पादन हेतु विपणन और संवर्धन सेवाओं पर प्रोत्साहन:** यह प्रावधान उन शुगर मिल्स जिन्होंने 28.02.2014 के बाद कच्ची चीनी का उत्पादन और निर्यात किया है, को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए है ताकि चीनी मिल्स किसानों को गन्ने की कीमत का बकाया भुगतान करने के स्थिति में हों।

6.02.08. **शुगर मिलों को रियायती ऋण सहायता देने सम्बन्धी योजना, 2015 के लिए ब्याज सहायता:** यह प्रावधान चीनी सत्र 2014-15 के लिए गन्ना किसानों के बकाया राशि का भुगतान करने के लिए चीनी उद्योग को सॉफ्ट लोन प्रदान करने के लिए है। सरकार ने इस ऋण के लिए एक वर्ष का स्थगन प्रदान किया है और वह इस ऋण पर 10 प्रतिशत तक ब्याज सहायता लागत वहन करेगी, जो की नोडल बैंक को अग्रिम के रूप में प्रदान किया जाना है। इस निधि को चीनी विकास निधि से पूरा किया जाएगा।

6.02.09. **चीनी मिलों को गन्ने के लागत क्षतिपूर्ति और किसानों को गन्ना मूल्य देयों का समय पर भुगतान सरल बनाने के लिए उत्पादन सब्सिडी:** चीनी उत्पादन के लिए पेराई किये गए गन्ने पर चीनी मिलों द्वारा गन्ने की खरीद पर आई लागत की भरपाई करने के लिए 4.50 रु. प्रति क्विंटल की दर से उत्पादन सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस सब्सिडी को मिलों की ओर से किसानों को सीधे भुगतान किया जायेगा और पिछले वर्षों के बकायों सहित उचित और लाभकारी कीमत (एफ. आर. पी.) के रूप में किसानों को गन्ना मूल्य देयों के भुगतान हेतु समायोजित किया जायेगा। इसके बाद बची हुई धनराशि, यदि कोई हो तो, मिल के खाते में जमा की जाएगी।

7. **भण्डारण विकास और विनियामक प्राधिकरण और खाद्य और भंडार से संबंधित अन्य प्रोग्राम:** (क) योजना प्रावधान, भण्डारण विकास और विनियामक प्राधिकरण जो की भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है, को अनुदान सहायता-वेतन एवं आईटी सक्षम प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और परक्राम्य भण्डागार रसीदों के ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के विकास पर होने वाले व्यय और स्थापना व्यय के लिए अनुदान सहायता-सामान्य प्रदान करने के लिए है।

(ख) गैर-योजना प्रावधान में निदेशन और प्रशासन (शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय, भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसन्धान संस्थान, केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला, गुण नियंत्रण कक्ष), अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद/अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद) के लिए प्रावधान शामिल है।

8. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण:** यह प्रावधान:

(क) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण से संबंधित चलाई जा रही योजनाओं जैसे प्रशिक्षण और टी.पी.डी.एस. लाभभोगियों में जागरूकता लाने के लिए है।

(ख) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन का सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण के लिए है।

(ग) खाद्य श्रृंखला और खाद्यान्नों की गुणवत्ता विनिर्देशन में लगे कर्मचारियों के गुणवत्ता कौशल को मजबूत बनाने से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं के लिए है।

(घ) घरेलू/वैश्विक बाजारों में खाद्यान्न से संबंधित अनुसंधान / निगरानी के लिए सलाहकार के भुगतान और विभाग में ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।

(ङ.) राज्य सरकारों व संघ शासित राज्यों की सरकारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अधिसूचना राज्य खाद्य आयोग की नॉन बिल्डिंग आस्तियों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए है।

9. **भंडारण और गोदाम:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों के द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान के साथ भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए है।